

Amdt. Ordinance, 1969

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI  
THENGARI) : The question is:

"That the Bill be returned." *The motion*  
*was adopted.*

**I. RESOLUTION SEEKING DIS  
APPROVAL OF THE GOLD (CON  
TROL) AMENDMENT ORDINA  
NCE, 1969 (NO. 6 OF 1969)**

**II. THE GOLD (CONTROL) AM  
ENDMENT BILL, 1969**

श्री जगन्मोहि प्रसाद यादव (बिहार) : मैं  
यह संकल्प उपस्थित करता हूँ कि :—  
“यह सभा राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे  
उपराष्ट्रपति द्वारा 3 जुलाई, 1969 को प्रख्या-  
पित स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश,  
1969 (1969 का संख्या 6) का निरनु-  
मोदन करती है।”

f] "That this House disapproves the Gold  
(Control) Amendment Ordinance, 1969 (No.  
6 of 1969), promulgated by the Vice  
President acting as President on the 3rd July,  
1969."

स्वर्ण नियंत्रण विधेयक जब से आया है तब  
से विवादास्पद बना हुआ है। यह भयंकर रूप  
से प्रभावी हुआ है। एक तरफ जहाँ इस देश  
के लाखों लाख लोग और इस व्यवसाय में लगे  
लोग प्रभावित हुए हैं, दूसरी तरफ इसको लाने  
वाले मंत्री भी प्रभावित हुए हैं। जिस समय  
स्वर्ण नियंत्रण कानून को प्रथम बार श्री मोरा-  
रजी देसाई लाए थे, इसके प्रभाव की बदौलत वे  
प्रथम बार मिनिस्ट्री से हटे और पुनः जब उन्होंने  
मेरे ही सामने इस सदन में इस बिल को उपस्थित  
किया था, तब हमने उनसे आग्रह किया था कि  
यह बिल ऐसा भयावह है, ऐसे गरीब लोगों पर  
प्रभाव डालता है, जिसका परिणाम मंत्री को  
भुगतना पड़ता है। एक कहावत है “निर्बल  
को न सताइए जाकी मोटी हाथ, मरे चाम  
की सांस सौ लोह भस्म हो जाय”। लाखों  
लाख गरीबों की उसांस में हमारे मंत्री श्री  
मोरारजी देसाई को पुनः मंत्रिमंडल से हटने के  
लिए बाध्य होना पड़ा। प्रधान मंत्री जो वित्त

ff ] English translation.

Mill, 1909

D. मंत्रालय का भार सम्भाले हुए हैं, मैं उनसे  
निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ी सुविधा  
के नाम पर इस गोल्ड कंट्रोल ऐक्ट के द्वारा  
उन लाखों लाख मुनारों के परिवारों को, उनकी  
जान को संकट में न डालें। राजनीतिक दांवपेच  
के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन तत्वों  
से वे बाहवाही लूट रही हैं, जिन विचारों को  
यह पता भी नहीं है कि उन्हें बैंक से क्या मिलने  
वाला है। लेकिन जिनको पता है, जो लाखों  
लाख लोग गोल्ड कंट्रोल ऐक्टसे त्राहि माम, त्राहि  
माम कर चुके हैं, उनकी त्राहि माम को पाहि  
माम में बदलने के लिए आप तैयार नहीं हो  
सके। आज वित्त मंत्रालय आपने सम्भाला है  
और यह आश्वासन दिया है कि आप इसके  
द्वारा कुछ प्रगति लाएंगी। हमारे दल ने  
स्वर्ण नियंत्रण विधेयक का शुरू से विरोध  
किया है। आज जब यह अवसर मिला है  
तो मैं यह कहता हूँ कि इस नए विभाग के  
मिलने के बाद आपको मौका मिला था कि  
थोड़ी सी सुविधा न लेकर सारे ऐक्ट को समाप्त  
कर दें जिससे लाखों लाख परिवारों का भाग्य  
बदले लेकिन वैसा नहीं हुआ। जब इन लोगों ने  
सुप्रीम कोर्ट में आपके ऐक्ट को चैलेंज किया  
और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं को असंगत  
मानकर इनवैलीडेट कर दिया, तो आपने उनको  
सुधारने की कोशिश की है और उसमें कुछ  
जोड़ने की भी कोशिश की है। अगर जोड़ने  
वाली धाराओं को भी चैलेंज किया जायेगा, तो  
पता नहीं वे धाराएं भी टिकेंगी या नहीं टिकेंगी।

अब मैं कुछ मूलभूत प्रश्नों के बारे में आपसे  
जानना चाहता हूँ। जिस समय इस बिल को  
लाया गया था, उस समय कहा गया था कि  
देश के सामने जो समस्या है, तस्कर व्यापार  
जो बहुत प्रबल रूप से हो रहा है, इस ऐक्ट के  
आने से वह तस्कर व्यापार रुकेगा, लाखों  
रुपया जो दूसरे देशों को चला जाता है वह  
नहीं जायेगा। क्या तस्कर व्यापार रुक गया?  
तस्कर व्यापार में जितने सोने को पकड़ा गया  
है उसी से मालूम हो जायेगा कि सोने का व्यापार  
बहुत ही बड़ा है। अगर उसको रोकने वाले

कर्मचारी ईमानदार होते, दक्ष होते तो उसमें भी सैंकड़ों गुना अधिक सोना पकड़ा जा सकता था। पहले सोना समुद्र के रास्ते से आता था। अब नेपाल सीमा से तस्कर व्यापार होता है। इसका भारत की अर्थ-व्यवस्था पर प्रबल रूप में प्रभाव पड़ने वाला है। पहले वहां तस्कर व्यापार होता था चीनी का, फाउन्टेन पेन का, ट्रांजिस्टर का, टेलीफोन का, टार्च का, लेकिन आज वहां तस्कर व्यापार होता है सोने का, चांदी का। नेपाल प्रसिद्ध था 17-18 करोड़ रुपये के गांजे के तस्कर व्यापार के लिए। आज वहां पर गिफ्ट पासल के द्वारा पता नहीं कौन-कौन सामान आता है, जिसकी खपत नेपाल में न होकर—भारत में होती है। भारत में खपत होने के कारण आज भारतीय व्यवसाय पर, अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सोना पहले जहां समुद्र के रास्ते आता था, अब पहाड़ की बगल से भी आ रहा है। तस्कर व्यापार आपके इस कानून से रुका नहीं।

आपने दूसरी इच्छा प्रगट की कि देश में सोना जेवर के रूप में बन्द कर दिया जाता है, जिसे कि व्यापार में लगा कर देश की सम्पत्ति का सम्बर्धन करना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। देश की जनता जो सोने का व्यवहार कर रही है, जेवर के रूप में या धनी जो सोने को ईंटों के रूप में या दूसरे रूप में घरों में रखते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह सोना आपके कानून बनाने से बाहर निकल आया? परिवार नियोजन पर आपकी सरकार लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करती है ताकि देश की आबादी न बढ़े। भगवान ने आदमी को जब भेजा है तो खाने के लिए जहां मुंह दिया है वहां काम करने के लिए दो शक्तिशाली भुजा भी दी हैं ताकि तुम अपना भरणपोषण और देश का भरणपोषण करो और सुरक्षा के लिए अपनी ताकत की आजमाईश करो, लेकिन सरकार तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी लोगों के हाथों को काम नहीं दे सकी, इसलिए उनके मुंह को ही बन्द करना चाहती है। ऐसे कामों के लिए आपकी सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। अगर सचमुच में आप चाहते हैं

कि जनता सोने का व्यवहार जेवर के रूप में न करे, सोना देश के व्यवसाय में, प्रगति में लगे, जिससे देश की सम्पत्ति की वृद्धि हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उसके लिए क्या किया? लोगों के मनोभाव को बदलने के लिए आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि फिर इस ऐक्ट को लाकर किस प्रकार आप चाहते हैं कि जनता सोने का जेवर के रूप में व्यवहार न करे। अगर आप भारतीयता से परिचित हैं, अगर भारतीय लोगों से आपका परिचय है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि सोना उसका सामाजिक अंग बन चुका है। खासकर इस कांग्रेसी शासन में जब रुपए का मूल्य कुछ नहीं रह गया है, आपके सिक्के का मूल्य 10 पैसे नहीं रह गया है, उस समय लोग सोचते हैं कि इस सोने का मूल्य ही प्रभावी है। तीन पंचवर्षीय योजनाओं में दो तरह के लोगों के पास ही सम्पत्ति की वृद्धि हुई है, एक हैं सरकारी अफसर जिनकी तस्करी रोकने के लिए और दूसरे लाइसेंस देने के लिए ऐसी जगहों पर रखा है जहां वे काले पैसे कमा सकते हैं। उस काले पैसे को न बैंक में जमा कर सकते हैं, न जाय-दाद खरीद सकते हैं, न मकान बना सकते हैं। उनके सामने सोना खरीदने के सिवा दूसरा चारा नहीं है। दूसरे बड़े बड़े सम्पत्ति वाले लोग हैं, जिन्होंने इन योजनाओं में लाखों, करोड़ों रुपए कमाए हैं और आपके इनकम टैक्स से बचने के लिए करोड़ों रुपयों का सोना खरीद कर अपने घर के नीचे बन्द करके रखते हैं। इसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? और अगर इसको रोकने के लिए, इस मनोभाव को बदलने के लिए आपने कुछ नहीं किया तो आपका यह ऐक्ट किस प्रकार से उसे रोक सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय परंपरा में शादी विवाह के अवसर पर लोग जेवर का व्यवहार करते हैं और दो बातों के लिए उनका व्यवहार होता है। पहले तो अपनी पुत्रवधू को सजाने के लिए सोने का लोण उपयोग करते हैं और उसके साथ ही उनका यह मंशा रहता है कि

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

इस रूप में एक बैंक वे अपने परिवार को दें जो उनको समय पर काम आये। आपके कानून के बदलते हुए स्वरूप को देख कर परिवार के लोगों को आशंका होती है और वे सोचते हैं कि कौन ऐसी चीज दी जाये कि जो समय पर परिवार के काम आये। आज आपने बिहार बैंक को स्टेट बैंक में मिला लिया है। बिहार बैंक में जिन लोगों का रुपया जमा है, आप उनकी हालत बिहार में जाकर देखें कि क्या हो रही है। उनके व्यवसाय रुक गये हैं, उनका कारबार रुका रहता है। आप कहते हैं कि हिसाब ठीक होगा तो रुपया देंगे। क्या इससे वहां के लोगों का काम चलेगा? आपके हर काम से लोगों की आशंका बढ़ती है और विश्वास नहीं बढ़ता है। जब तक लोगों में आपके प्रति विश्वास नहीं बढ़ेगा तब तक आपका कानून कैसे उन लोगों के लिए लाभदायक होगा?

यद्यपि यह छोटा सा बिल लोगों को सुविधा के लिये है, किन्तु यदि आप लोगों को वास्तव में सुविधायें देते, तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। कहता हूँ कि चलो, जल्दी नहीं तो देर से ही सही, अंधेरे को दूर करने की ओर सरकार का कदम तो बढ़ा और वह प्रशंसनीय है। किन्तु मुझे यह जानकर अफसोस होता है कि सरकार को भी यह पता नहीं होता कि देश में कितने सोने के व्यवसायी हैं। अगर सरकार सोचती है कि जो सोने चांदी की दुकानें करते हैं वे ही सोने के व्यापारी हैं, तो इस व्यवसाय को अपनाने के लिये जो कोयले के या दूसरे धंधे के लोग आना चाहते हैं उनके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। बिहार की विधान सभा में इस प्रकार का एक प्रश्न आया था और सरकार ने उनको कुछ सुविधायें देनी चाहीं, लेकिन वह स्वर्ण नियंत्रण कानून से बंधे थे। वे सुविधायें बड़े व्यापारियों तक को तो क्या, छोटे सुनारों तक को नहीं मिल पायीं। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के हर कदम के पीछे जनता का विश्वास रहना चाहिये। यही लोकप्रिय सरकार का सबसे बड़ा आधार है और इसी आधार पर कोई लोकप्रिय सरकार

शासन करती है। इसी पर जनतंत्र चलता है और उसके आधार पर इस कानून का क्या महत्त्व रहता है?

मैं इसी संदर्भ में आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। अब तो इस कानून को बने हुए कुछ दिन हो गये हैं और सरकार को भी इसका कुछ अनुभव प्राप्त हुआ होगा। सरकार इसका अनुभव ले रही है। मैं उससे जानना चाहता हूँ कि गोल्ड कंट्रोल ऐक्ट में जो डीलर्स इसे डील करते हैं, उन्होंने जब चैलेंज किया तो कुछ सुविधायें उनको मिल गयी, लेकिन सोने का व्यवसाय करने वाले छोटे-छोटे जो सुनार थे, उनको सुविधायें देने के बारे में सरकार ने कोई विचार क्यों नहीं किया? आपने जो ऐक्ट यहाँ रखा है उसके दो चार पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके चलते जो आपके अधिकारी होंगे वह किस प्रकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे उस संबंध में मैं आपके सामने क्लोज 6(ए) की दो, तीन पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ:

"... as may be prescribed in this behalf and after making such enquiry in respect of those matters as he may think fit, specify that the licences should be issued."

आपके अधिकारी उसको तब तक फिट नहीं मानेंगे जब तक उनकी पाकेट गर्म नहीं हो जायेंगी और ऐसे अधिकारियों के द्वारा छोटे-छोटे व्यापारी जो उनकी पाकेट गर्म नहीं कर सकेंगे, उनको लाइसेंस मिलने में कितनी गड़बड़ी होगी, इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। जो बड़े हैं वे तो आपके अधिकारियों से मिल कर तस्करी का व्यापार कर लेते हैं और उसके साथ ही वे दूसरे व्यापार भी कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे हैं उनके लिये कोई निदान नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपने जो अनुभव प्राप्त किया है, उसके आधार पर आप बतायें इस सदन को कि आप इस कानून के द्वारा सरकार को, राष्ट्र को और जनता को क्या लाभ हुआ और क्या यह सही नहीं है कि इस कानून के चलते जो सीधे सादे जीवन बिताने वाले सुनार थे वे उजड़ गये। क्या आपके इस कानून ने

उन मुनारों को बाध्य नहीं किया कि वे तस्करी का व्यापार करें और क्या वे मजबूर नहीं हो गये कि अगर वे जीना चाहते हैं और परिवार को जिन्दा रखना चाहते हैं, तो वेईमानी भले ही हो, लेकिन वह वेईमानी ही करें। क्या आपने देहात में रहने वाले मुनारों को सदा के लिए पायमाल नहीं कर दिया? आपने इतना कठिन कानून बनाया है। क्या आप समझते हैं कि इस कानून का इंटरप्रेटेशन छोटे-छोटे लोग, जो देहातों में या शहरों में रहते हैं, जो अतपढ़ हैं, कर सकेंगे और वे इसको समझ सकेंगे? क्या इस से जो लाभ या हानी उनको होगी उसको वे समझ सकेंगे? और अगर नहीं तो आप मुझे बतायें कि सचमुच में क्या आपको इस कानून से कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है जन जीवन को देख कर और अगर आपको जन जीवन को देख कर कुछ भी अनुभव प्राप्त हुआ होगा, तो मैं मोचता हूं कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह कानून या तो बिल्कुल समाप्त कर देने योग्य है या यह आमूल-चूल परिवर्तन चाहता है। जो इस बिल का असली मंतव्य है कि देश में तस्करी न हो, सोने को छिपा कर रखने की प्रवृत्ति खत्म हो, सोने का सदुपयोग हो और देश का रुपया बाहर न जाय और सचमुच में आप अगर इसको कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो आपको तस्करी को तो रोकना ही होगा। चाहे जैसा भी हो और उसके साथ जो काला धन बढ़ रहा है उसे भी आपको रोकना होगा। आज लोग काले धन से इस पीले धन सोने को खरीद कर रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सोने का उपयोग वास्तविक ढंग से हो तो आपको इसका प्रारूप तैयार कर जनता को देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यह भी करना पड़ेगा कि छोटे लोग जो सोने को बैंक के समान व्यवहार करते हैं, उनके लिए बैंकों की सुविधा सही तरीके से गांव-गांव में करनी पड़ेगी और उन्हें इसके लिए समझाना पड़ेगा और इसके पहले आपको अपने दिल और दिमाग को दुकस्त करना पड़ेगा।

अंत में, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस बिल के चलते जो प्रभाव मुनारों पर पड़ता है,

उससे उसकी हाथ निकलती है। उसके कारण ही हमारे श्री मोरारजी देसाई का राजनीतिक जीवन संकट में पड़ा और वह मंत्रित्व से तो गये ही। ऐसा न हो कि यह स्वर्ण नियंत्रण ऐक्ट हमारे वर्तमान वित्त मंत्री को भी अपने चक्कर में ले ले। आज जैसी स्थिति कांग्रेस में हो रही है वह अजीब है। अगर सचमुच प्रजातंत्र के सिद्धांत को मान कर कांग्रेस चली होती, तो आज कोई भी अधिकार उसे नहीं था यहां बने रहने का। हमारे वित्त मंत्री, जो कि हमारी प्रधान मंत्री भी हैं, उनके प्रत्याशी सीधे चुनाव में हार चुके हैं। कुछ हमारे कांग्रेसी बंधु यह कहने का दावा कर सकते हैं कि श्री गिरी भी हमारे प्रत्याशी हैं, दबे दबे वह यह बात कह जाते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड ने श्री संजीव रेड्डी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया, उन प्रत्याशी को घोषित किया और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उनका प्रस्तावक बन कर, यह साबित किया कि वे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पार्लियामेंटरी बोर्ड के भी और कांग्रेस के भी। और आज वह कांग्रेस का प्रत्याशी हार चुका है और हार चुका है इन दोनों सदनों में भी, इसलिये सरकार को कोई भी अधिकार नहीं था कि वह प्रशासन को अब भी अपने हाथ में रखे, उसे विश्वास प्राप्त करने के लिये रिजाइन करके, इस्तीफा दे करके, विश्वास प्राप्त करना आवश्यक था, लेकिन यह सरकार किसी कारण से रिजाइन करना नहीं चाहती। जब अपनी जरूरत होती है, तब यह डेमोक्रेसी की दुहाई देती है। दल-बदल की बात पर, डिफेक्शन पर, पता नहीं किस मुंह से यह सरकार कानून बनाने को आगे बढ़ती है। यह सरकार अच्छे अच्छे भाषण देने का प्रयास करती है, लेकिन डिफेक्शन का इतिहास बताता है कि कांग्रेस में डिफेक्शन शुरू से हो रहा है। लेकिन जब तक लोग कांग्रेस में डिफेक्शन करते रहे तब तक तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब कांग्रेस से डिफेक्शन प्रारंभ हुआ, तब उनको चिन्ता हुई और मेरा कहना है कि जब सदन में डिफेक्शन के बारे में प्रस्ताव मंत्री जी लाये थे, उसी समय कांग्रेस के मंत्री

[ श्री जगदम्बो प्रसाद यादव ]

प्रधान मंत्री समेत डिफेक्शन किया था। पता नहीं कि इस सरकार का सचमुच में मारल कैरेक्टर क्या है, नैतिक स्तर क्या है। इसीलिये मैं कहना चाहता हूँ कि सचमुच में यदि वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री इन गरीबों की आह से बचना चाहते हैं तो यह गोल्ड नियंत्रण अमेन्डमेंट ऐक्ट को समाप्त करें।

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C.  
SETHI): I move:

"That the Bill to amend the Gold  
(Control) Act, 1968, as passed by the Lok  
Sabha, be taken into consideration"

I have heard with great attention the speech made by Mr. Yadav. The measure before the House is not the Gold (Control) Act in its original form but a Bill amending certain provisions of the Act and the necessity has arisen on account of the Supreme Court decision. Therefore the merits or demerits of the Gold (Control) Act, as a matter of fact, do not form part of the discussions. Here we are limiting the subject to certain clauses which have been amended keeping in view the Supreme Court decision but when I come to the reply during the course of the debate, then I will take up some of the major points which are basically connected with the Gold Control policy also. Now in my introductory remarks, I would only like to limit myself to the main provisions with which this Bill deals.

The Gold (Control) Act was passed by the Parliament in 1968 and since then the matter was challenged before the Supreme Court by various persons. Therefore I would like to clarify that as far as the Supreme Court judgment is concerned, the Supreme Court has unanimously upheld the legislative competence of Parliament to enact the Gold (Control) Act. As far as the challenge to the Act is concerned, the Supreme Court has held that the basic Act stands. I would quote from the judgment of the Supreme Court:

"It follows, therefore, that in enacting the impugned Act the Parliament was validly exercising its legislative power in respect of matters covered by Entry 52 of List I and Entry 33 of List III."

The Court further observed:

"Parliament is competent to legislate in regard to the subject-matter of the impugned Act."

Therefore, the basic Act of 1968 has not been invalidated by the Supreme Court. The Supreme Court during the course of the judgment struck down some of the provisions of the Act and they are: sections 5 (2) (b), 27 (2) (d), 27 (6), 32, 46, 88 and 100 and they were found to be unreasonable where the administrative authority, according to the court, had delegated much more in the hands of the officers and, therefore, on account of this reason and various other reasons, the Supreme Court observed that these provisions were not in order and they have struck it down. Therefore now we are coming forward with this Bill with two or three types of amendments. One is, to set right those sections which have been invalidated by the Supreme Court and to amend them accordingly; secondly, even if the Supreme Court has not given any judgment with regard to some of the other provisions if they are reading like the provisions which have been struck down by the Supreme Court, we have ourselves taken the responsibility and duty to amend those provisions and sections. This is the second set of amendments in this Bill. Thirdly we have come before the House with some clauses which are giving certain more clarifications and certain more facilities to the various interests rather than the dealers or goldsmiths, etc. This is all that the present Bill says. When we will come to the amendments, I shall try to explain as to the various points raised by Mr. Yadav as to how the Gold Control came to be there and whether the Gold Control measures have to some extent succeeded. He raised the point about smuggling. I would try to explain what measures we have taken and whether we have succeeded there or not. Of course in the end while speaking on the Resolution, Mr. Yadav brought in many extraneous matters. I am not able to appreciate how the Presidential election arises out of the Gold (Control) Act but somehow or other Mr. Yadav had some feelings and he wanted to express them and he found this a suitable opportunity to spell out whatever he had in mind with regard to the election. He is welcome to do whatever he likes but I can assure him that whatever he has said regarding the Presidential election has no validity whatsoever to the Gold (Control) Bill which is before the House.

With these words, I commend the Bill for consideration.

*The questions were proposed.*

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि मंत्री महोदय का इस पर कुछ विचार व्यक्त हो जाता, इस पर कुछ विचार हो जाता तो मुझे कुछ संतोष भी होता और यदि संतोष नहीं होता तो मैं अपनी कुछ बातें फिर उनके सामने रखता। खैर, मैं इस मौके पर मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि शायद मेरे द्वारा उठाये गये विषयों को विषयांतर समझ कर वह अलग करना चाहते हैं।

**श्री पी० सी० सेठी :** नहीं, मैंने नहीं किया।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** मैं उन विषयों को इसमें जिस प्रकार से लाया था उसको मंत्री महोदय विषयांतर समझ सकते हैं लेकिन जब विषय का सूत्रपात हो जाता है सदन में तो उसके इर्दगिर्द जितने विषय और चीज है उसका उसमें समावेश हो जाता है। सवाल यह है कि इस ऐक्ट का जिन लोगों पर प्रभाव पड़ता है उन लोगों की जो बात है, जिनका प्रतिनिधित्व हमें करना है उनकी वाणी को इस सदन के द्वारा सरकार के कानों में पहुँचाना हम अपना परम पुनीत कर्तव्य समझते हैं और इसलिये आपके कर्तव्य की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित किया। मैं चाहता था कि सचमुच में आप विश्वास दिलायें कि आप जनतंत्र के प्रतिनिधि हैं और यहां के प्रशासन की पद्धति प्रजातंत्रीय है ताकि प्रजा को आपके कामों पर, आपके विधेयकों पर पूरा पूरा विश्वास होता। आप अपना राजनैतिक चरित्र या प्रशासनिक चरित्र जिस प्रकार प्रकट करेंगे उसी प्रकार मैं आपके भाव प्रकट होंगे।

अब मैं दो एक बातें प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इसके सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इसमें अमेंडमेंट लाये हैं उस पर आप भी विचार करें कि जितना सोना रखने की छूट आपने सुनारों को दी है उससे उनका काम नहीं चलता क्योंकि सुनारों का जो रोजगार है वह खासकर उस समय अत्यधिक चलता है जब कि शादी,

विवाह के लगन होते हैं, साल में जितना सोना रखने की आपने छूट दी है उतना सोना उनके पास हो जाता है तो उसका काम चल जाये। जिस समय शादी का 'लगन होता है' बिहार का मुझे अनुभव है, कभी कभी लगन इतने प्रचंड रहते हैं कि एक एक आदमी के यहां पन्द्रह पन्द्रह, बीस बीस लोग जेवर रखते हैं। जितने सोने की आपने छूट दी है उस सोने की छूट में आप 15 लोगों को जेवर बनाने की सुविधा नहीं दे सके हैं इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। अगर स्वर्णकार के जिम्मे पन्द्रह आदमियों की लिस्ट हो तो उस हिसाब से उतना सोना रखने की उसको सहूलियत मिलनी चाहिये जिससे कि वह सभी ग्राहकों के जेवर बना सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आप स्वर्ण नियंत्रण कानून के द्वारा स्वर्ण नियंत्रण को सिर्फ सोने का व्यवसाय समझ कर टूट न करें। मैं चाहता हूँ यह जो परम्परागत पुरानी भारतीय कला है इसको संरक्षण मिले, जैसे आपने और कलाओं की सुरक्षा की गारण्टी दी है। उसी तरह से इसको भी आप कला के रूप में स्वीकार करें। आप ऐसी व्यवस्था करें कि स्वर्णकार सोने के आभूषण ही नहीं बनाएं बल्कि सर्वोत्कृष्ट कला की चीज प्रस्तुत कर सकें। आपने देखा होगा कि आज विदेशों से अपने भारतीय धातु की बनी अनेक चीजों की मांग बड़े प्रबल रूप से आ रही है। हमारे देश में जो विदेशी यात्री आते हैं वे यहां के सोने के आभूषण को बड़े शौक से, दिलचस्पी से पहनते हैं। जिस तरह से आप टूरिज्म को अपने व्यवसाय की दृष्टि से बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं उसी प्रकार अगर आप उन स्वर्णकारों को एक दिशा देते तो देखते कि किस प्रकार विदेशों से उनकी बनाई चीजों की मांग आती और आप अपने व्यवसाय को सब जगह घुमाते तो उसके लिये फारेन मार्केट में जाने की भी सुविधा हो जाती। इससे एक नई दिशा मिलती जिसमें वह आगे बढ़ सकते थे। लेकिन आपने वह भी नहीं किया। मैं चाहता

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

हूँ आप स्वर्णकारिता को कला के रूप में स्वीकार करें और कला के रूप में स्वीकार करने का निदान दूँ।

मैं आपसे एक और अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जब भी सुविधा देने की बात करते हैं, चाहे वह सोने के व्यवसाय की बात हो तो बड़े लोगों को सुविधा की बात करते हैं। लेकिन मैं छोटे-छोटे लोगों की बात करता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सोने के व्यवसाय में मदद करने वाले कम से कम दस प्रकार के और लोग भी होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सोने को ढालते हैं, कुछ लोहे के पत्तर बना कर देते हैं। आप तो बड़ी बड़ी दुकानों में गये होंगे, लेकिन अगर आप किसी मुनार के यहाँ जेवर बनाने गये हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ कोयले से भी काम करने वाले होते हैं। सोने को ढालने के काम में कोयला आता है और कोयले की भी बिक्री होती है। इस प्रकार इस तरह के आदमी सोने के धंधे में काम पाते हैं। तो उनके लिये क्या कभी आपने विचार किया। अगर आप चाहते हैं आपका तिजारत बढ़े और इसके लिये मौका मिले और आप उनको सुविधा देना चाहें तो इस दृष्टि से अगली दफा आप स्वर्ण नियंत्रण कानून में कुछ न कुछ ऐसा अमेंड-मेंट लायें जिससे सभी लोगों को लाभ मिल सके।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) : I would like to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : Members have already spoken. I am sorry you were not here. Otherwise I would have called you first.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : I am sorry. I did not expect this Bill to be reached so soon.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : I am also sorry. I cannot help. The Minister has risen to reply.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Is he replying to the debate?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : Yes.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Well, I cannot behave like Mr. Rajnarain. I cannot do it, Sir. If Mr. Rajnarain had shouted over this everybody would have yielded to his shouting.

SHRI P. C. SETHI : Sir, as far as the gold policy of the Government of India is concerned, it is known that import (if gold has been prohibited in i- 1939. then, Sir, in the year 1962-63, after the Chinese invasion, under the Defence of India Rules it was thought necessary that there should be some restriction on the manufacture of gold ornaments of 22 carat purity, and therefore it was decided that only 14 carat gold ornaments would be allowed to be manufactured. Then, Sir, later on, after a couple of months, on account of the representations made both outside and inside the House and the views expressed by hon. Members at that period of time, it was considered necessary, as far as 14 carat purity is concerned, that it should be done away with, and since then—I would like to make it clear—as far as the 14 carat purity question in the manufacture of gold ornaments is concerned, that is no more there. Now, Sir, as far as the possession of gold ornaments is concerned, there is no restriction whatsoever on the possession of gold ornaments. Similarly, as far as the dealer or the goldsmith is concerned, he can certainly take to manufacture of gold ornaments, and there is no difficulty with regard to that. Then, Sir,

the possession of gold bars is concerned, certainly pure gold is not allowed to be possessed by any individual. But as far as ornaments are concerned, if anybody possesses, if any individual family possesses ornaments weighing more than 4,000 grammes that is ornaments worth round about Rs. 60,000, then he has certainly to make a declaration, and whenever there is any change in the quantity, the declaration has to be made. But there is no restriction whatsoever on the possession, Then as far as the dealer is concerned, then is no restriction on the possession of gold bars of standard quality, and the dealer can possess them, and during the manufacture gold ornaments, if the bar is melted, it is provided in the Bill as to what extent pure gold could be possessed by the dealer. Similarly, Sir, as far as the...

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अभी माननीय यादव जी ने जो कहा था कि जो मनुफेक्चर करने वाले हैं, मुनार लोग, अगर उनके पास एक साथ पचास

आदमी आ जायें जेवर बनवाने के लिये और उसके लिये उनके पास काफी क्वाण्टिटी हो जाये सोने की तो क्या उसके लिये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि सीजन चलता है, शादियों के लग्न होते हैं, तो उस समय बहुत रश हो जाता है जेवर बनाने वालों का। यदि एक ही सुनार के पास काफी संख्या में ग्राहक आ जायें तो क्या इस प्रकार की कोई सीमा है कि जितना जेवर बनाना चाहे बना सकता है। इसका क्लेरिफिकेशन वह भी चाहते थे मैं भी चाहता हूँ।

**श्री पी० सी० सेठी :** जहां तक प्योर सोना रखने का ताल्लुक है, एक डीलर कितना रख सकता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन है, एक सुनार कितना रख सकता है उस पर रेस्ट्रिक्शन है। मैं अभी आपको बता देता हूँ . . .

**श्री मानसिंह वर्मा :** 500 ग्राम का है।

**श्री पी० सी० सेठी :** जहां तक सुनार का ताल्लुक है, उसको 300 ग्राम तक सोना रखने की उसके अंदर छूट है। जहां तक डीलर का ताल्लुक है, डीलर को भी एक निश्चित मात्रा में सोना रखने की इजाजत है। उससे ज्यादा उनको रखने की इजाजत नहीं है। लेकिन जहां तक ऑनमिण्ट का ताल्लुक है, ऑनमिण्ट में कोई प्रतिबंध नहीं है अगर बनाने वाला पुराने जेवर लाता है। किसी डीलर या सुनार का यदि कोई बिजनेस है उसका तो कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन उसको मैटीरियल खरीदते समय, उसके पास प्योर सोना कितनी मात्रा में रहे, उस पर प्रतिबंध है।

**श्री मानसिंह वर्मा :** तो इसका अभिप्राय यह है कि सुनार एक समय में 300 ग्राम से अधिक नहीं रख सकेगा।

**श्री पी० सी० सेठी :** जहां तक सोनार का ताल्लुक है प्योर गोल्ड एक समय में उतना नहीं रख सकेगा लेकिन जहां पहले यह सुविधा 100 ग्राम की थी, बाद में वह 200 ग्राम की हुई, और अब यह सुविधा 300 ग्राम की है। यह

मांग की गई कि 300 ग्राम सोना रखने की सुविधा छोटे सुनारों के लिये हो जो कारोगरी का काम करते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। वह काम समाप्त करने के पश्चात् वह दूसरा सोना फिर गला सकता है।

**श्री मानसिंह वर्मा :** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, दिक्कत तो 100 ग्राम में भी नहीं थी और 300 ग्राम करने के बाद भी नहीं होनी चाहिये किन्तु यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जब बहुत बात सारे ग्राहक आयेंगे ऐसी हालत में 300 ग्राम की सीमा रखी जाये। यह बात समझ में आने वाली नहीं है। इतना स्पष्ट होना चाहिये कि इसका रखना माना जायेगा या जेवर का बनाना माना जायेगा।

**श्री पी० सी० सेठी :** जहां तक शुद्ध सोना रखने का संबंध है कोई भी व्यक्ति 300 ग्राम से अधिक सोना नहीं रख सकता, मगर जेवर के फार्म में वह सोना रख सकता है।

What I was trying to explain is this. As far as the present measure is concerned this is only a measure which provides certain guidelines and controls with regard to possession of gold ornaments by the private public, with regard to possession of pure gold by the private public. with regard to the quantity which could be possessed in the form of pure gold by dealers, with regard to the quantity which could be possessed by a *sonar*, etc. This is only to control these things. There is no restriction on the purity of gold ornaments which are to be manufactured; there is no restriction on the possession of gold ornaments except to the extent that one cannot hold more than 4000 grammes per family and if it exceeds this limit it has to be declared. Therefore there is no difficulty whatsoever for the normal trade channels.

Now the position with regard to gold is this. As far as original production of gold in our country is concerned, it is very limited. It is either available from the Kolar gold mines or from the Hutti mines. As far as the Hutti gold is concerned that is actually going for industrial purposes and therefore it is not possible to divert it for ornament purposes. As far as the gold manufactured from the Kolar gold mines is concerned it goes to the Reserve Bank. That also does not come to the market. But between the dealers who are thousands



[Shri P. C. Sethi]

in numbers and between the *sonars* who are also about 2 lakhs and 50 thousand it is considered that old ornaments will come for repairs and some quantity of gold will be available from here and there and with that it will go on. It is a well known fact that in spite of all these restrictions smuggling of gold is taking place. The hon. Mr. Yadav has mentioned that smuggling of gold takes place not only from the sea routes but now also on the Nepal border. As far as our information goes there is no smuggling of gold or silver on the Indo-Nepal border. Smuggling of course is there but it is of a different nature. As far as smuggling of gold and silver is concerned it is mostly on the western coast and it is from Dubai. We are taking all possible anti-smuggling measures ; we have recently amended the Customs Act and have put all sorts of restrictions on the movement of silver. We are providing hovercraft to our customs people for keeping a watch. We are giving them modern equipment and all other things which are necessary for the purpose.

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर जनवरी और मई के महीनों में फौरिसगंज में जो चीजें स्मगलिंग की पकड़ी गई थीं, जो कई लाख रुपयों की थीं, क्या मंत्री जी ने उन चीजों की ओर ध्यान दिया कि उसमें सोना भी था या नहीं ? जिस तरह से नेपाल से चीजें स्मगल होकर भारत में आती है तो सोना भी उसके साथ आ रहा है ।

**श्री पी० सी० सेठी :** नेपाल और बिहार के बॉर्डर में कौन कौन सी चीजें पकड़ी गई हैं, इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है । मैंने कहा कि आम तौर पर सोने और चांदी का तस्कर व्यापार वेस्टर्न बॉर्डर में होता है । इण्डो-नेपाल बॉर्डर में इस चीज का व्यापार नहीं होता है । एक दो घटनाएं हो सकती हैं ।

I was trying to say that as far as smuggling is concerned, it is there and this smuggling is a drain on our foreign exchange resources. Therefore from all points of view it was considered necessary that there should be some restriction on gold ornaments or on the use of gold. Of course our country has got centuries-old habits of using gold ornaments and therefore unless there is proper social education it is very difficult to completely stop it but

at the same time the necessity is there. As far as the parent Gold Act is concerned it is there on the statute book from 1968. Now it is anybody's guess, though it is a short period to judge, whether the Gold Control Act has succeeded or not. I said the other day in the other House also that it is open for that House and this House as well as for the Government to consider whether the Gold Control Act of 1968 in its original form has succeeded or not. That will be a separate matter for consideration. Here as far as this Bill is concerned we have a limited purpose which I have explained while introducing the Bill. Therefore I have nothing more to add at this stage except to say that the merits of the Gold Control Act need not be gone into. The Supreme Court Judgment pointed out that excessive powers had been given to the administrative authorities and to that extent we have tried to correct it. Now it has been provided that with regard to the rules that will be framed both with regard to goldsmiths and with regard to dealers, they will not be arbitrary rules. We will place even the rules before the hon. House so that it can approve of them or disapprove or direct us to amend them. It is only on the basis of the rules thus approved by Parliament that we shall be basing our policy and control. The excessive administrative powers which were supposed to be there according to the previous Act in the hands of the various administrative authorities have been done away with and the present Bill is only to amend that situation.

THE VICE-CHAIRMAN - (SHRI D. THENGARI) : The question is:

"That this House disapproves the Gold (Control) Amendment Ordinance, 1969, (No. 6 of 1969), promulgated by the Vice-President acting as President on the 3rd July, 1969".

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : The question is:

"That the Bill to amend the Gold (Control) Act, 1968, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration." *The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

*Clauses 2 to 15 were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

5106

SHRI P. C. SETHI : Sir, I move: "That the Bill be passed."

*The question was proposed.*

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Mr. Vice-Chairman, Sir, the history of the Gold Control Bill has had a chequered career in this House as also in the courts. It is not my purpose to go over all that. The Minister has said that the purpose of this Bill is limited to a certain extent; well, I am glad it is. But when the original motion was brought the excuse for bringing this Bill was to remove the lure for gold. This is attempting the impossible because every ordinary student of economics knows that gold has been accepted as a form of international currency all over the world because of its intrinsic quality and value and I think if the Government is trying to undo this, it is attempting the impossible. Even in the Soviet Union—whether they have currency or not—the roubles which they use in their international deals are specified to contain so much of gold value. Whether you have gold currency or not is a different matter. Whether you go by rupee payment or by anything else every currency is specified to be of so much gold value. That shows what importance gold has in the matter of value and currency and the Government is trying to do the impossible by trying to remove this.

As far as the limited purpose of this Bill is concerned I do not think it meets the objection that has been raised from this side of the House.

It hurts the self-employed ordinary craftsman. I know that some little concessions have been given, but as my friend here pointed out, they are not workable. The goldsmith may get ornaments to be made or repaired during a season and for that period the amounts specified here are not practical. Let me ask Members on the opposite side, on the Treasury Benches. I am sure they have marriages in their houses. Do they consider this limit satisfactory for the marriages that take place in their own houses? Let them be honest and say so. Then, I would withdraw my objection to the Bill, but that is not the case. This is not a practical limit that is put in here. I would like the Government to encourage honesty and let people say honestly that this is not enough for a normal middle-class marriage or ordinary class marriage and so much gold is required. Then, that should be permitted. It may be that so much gold may be in the family or it may have to be

bought, but then if you have these impractical limits, it hurts the trade. It hurts particularly the small, self-employed goldsmith. It does no benefit. It encourages corruption. We hear a number of cases of gold being caught while being smuggled. How much do we not hear of? It is common knowledge and it is said everywhere that for so many cases, one case is caught, so that the police may at least show something on paper that they are doing something. What goes under the observation of the police is something more, larger than these figures. I do not blame the police. If you ask them to do the impossible, they cannot accomplish it. Therefore, Government should realise the futility of such measures and not come forward with such impractical ones. After all gold has been used in this country for years for many purposes, including ornaments. Government has not been able to provide banks or places where people can keep their money in safety. Therefore, people keep it in gold perhaps in their house and perhaps they keep it on the person of their family members. It is one method of keeping their savings. As long as there is no other substitute, such measures do not meet the requirements of the situation and basically our opposition is to a measure of this type, which is not practical. The few modifications that have come about here are as a result of the Supreme Court's ruling. Yet the Government does not seem to understand that this is not the right way of doing it. Well, we can only oppose such Government measures.

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, I am i'Ot a traditionalist in the style of Mr. Dahyabhai Patel.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Then, why do you not come in suit? Why do you come in your traditional dress?

SHRI A. P. CHATTERJEE: I do not believe that because the women of India have been wearing gold ornaments, for ages, they must continue to wear them even now. If I were a traditionalist, perhaps I would have asked: Why not paint our bodies as the cavemen did? That also would have been a continuing tradition, because the cavemen at least for thousands of years were painting their bodies in a grotesque fashion. At least they thought it to be an ornament. But that is not a point on which I am going to speak, not from the point of view of tradition, because tradition has often to be broken in order that one might have glimpse into the vista

[Shri A. P. Chatterjee] of the future. I have to speak on the Bill rather from another point of view and that has been harped upon by some of the speakers who preceded me. In the words of the hon. Minister also we found the same note—though in a very muted manner but then the tone was there—of despondency, the tone (that perhaps the Act has failed. Now, that is the point which I want to emphasise. After all, I am speaking on the Third Reading of the Bill and at this stage we may not say so much on the merits of the Bill as we may say about—the future projection of the thought-process which is contained in the Bill. Now, the point is this. Has the Gold Control Act succeeded? Now, it has succeeded in making many young goldsmith commit suicide. The history of the Gold Control Act is a history of starvation, a history of suicides, a history of frustration for many a family of goldsmiths. I am coming from a State where scores of persons committed suicide by drinking nitric acid and that happened also throughout India. Who does not know that this was a pet child born out of the brain of Mr. Morarji Desai, the then Deputy Prime Minister and Finance Minister? Now, he wanted to plug the hole created by devaluation and the fall in foreign exchange earnings caused by devaluation. Also, he wanted to plug the hole which was caused in the economy of the country in deficit financing, but then a deficit financing and any fall in the foreign exchange earnings cannot be plugged, made up or compensated by this kind of Act which has been put on the Statute Book, in 1968. It has already passed through sea change so to say and ultimately it is not what it was. Again, it has failed in its purpose as has been said by certain hon. Members and as has almost been admitted by the hon. Minister himself. who said it is for the House and also for the Government to consider it. Well, Mr. Sethi was speaking as if he was not a part of the Government. Even what the Government will consider, he does not know, because he said that it is for the Government to consider whether the Act has failed or not. I do not know what he meant, but actually this is what was apparent from what he spoke, that he is also not happy about the success of the Act. Success has eluded him. That is quite clear. Therefore, what is the use of the measure, when it has failed? It would have been all right if an ideal state of affairs could have been brought about by which the women of the country would not be wearing any gold ornament and the gold in the country would be put in the vaults of the banks.

If gold is not used in the fashion in which it is being used now, perhaps it would have been very good for all of us. Perhaps it would have been an ideal condition, but then that ideal condition is lacking now. Now, putting so much expenditure on the administrative machinery which will be needed in order to put this Gold Control Act into operation, is a waste. Knowing these administrators, these licences and all the paraphernalia you need, knowing human character, knowing the character of the bureaucrats, I can say these licences and fees create a corruption ring. The persons who wish to get the licences can get the licences by some amount of pressure or by some amount of influence. It may be monetary influence, influence of gold or other influence, but this is the position. Why should we put so much expenditure into this machinery for implementing the Gold Control Act, so that the pet child of Mr. Morarji Desai may still continue to gasp for some time more? It is really gasping, nothing but that, because it has not much of life left in it. Now, that is one thing.

Secondly, after all the fall in foreign exchange earnings cannot be met by virtue of this kind of Gold Control Act. What about the businessmen who always defraud us of foreign exchange by fraudulent means by indulging in under-invoicing and over-invoicing?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: How much did you lose by devaluation?

SHRI A. P. CHATTERJEE: That could be immediately checked, but that was not done. That is not being done. But it has not as yet been so much insistent or so much strict in regard to businessmen who defraud India of foreign exchange earnings by under-invoicing and over-invoicing.

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu): Do you not think that they give some sums to the Congress fund?

SHRI A. P. CHATTERJEE: I do not think, but today or tomorrow we are hoping for the better. Secondly, Mr. Vice-Chairman, this devaluation business, who did it? That 'Troika' or three musketeers. Mr. Subramaniam, Mr. Chowdhury, and—what other man?—the three of them on the 4th June, 1966, when Parliament was not in session took a secret decision to devalue, and for what purposes? So that our export earnings will go up. But the history of our export earnings has shown

t-hat devaluation has depressed our exports and has not increased our exports. You devalue without consulting Parliament, you devalue because Mr. Bell of America has asked you to do it, you devalue because the International Monetary Fund had brought pressure upon you. To plug all these things you bring this Gold Control. The effect of this is that young goldsmiths committed suicide by drinking nitric acid. The purpose of the Gold Control Act is absolutely spoiled. Even the Ministers who wax eloquent will make a present of gold ornaments on the wedding of their near and dear ones. Even though Gold Control is so much in the air, everybody violates it from the top men to the bottommost men.

Therefore, Mr. Vice-Chairman, I would not take much time over this. I think that this is a dead Act. Merely you are trying to inject vitality into it. You are trying to whip a dead horse alive. It is as dead as mutton. What is the use of spending so much and making this machinery alive which will mean so much corruption—I use the word 'corruption'—and so much expenditure? It is better as the hon. Minister has said, for the Government to consider whether this Act has failed or not. I think it is high time the Government considered it. Let this Act be scrapped and some other thing brought in, but not this one.

SHRI P. C. SETHI : Mr. Vice-Chairman, it would be of interest to the hon. House to know that free ownership and free trading in gold is not permitted in most of the countries including the U. S.A. and the U. K. which are considered to be the most affluent and advanced countries. But, Sir, as I have said earlier, the lure of gold or the desire to possess gold ornaments has been there in our country. In spite of all this it was considered necessary that there should be some restriction on the manufacture of gold ornaments; after the Chinese aggression that was considered necessary. That is why the 14 carat restriction was put. I am unable to understand the argument of Mr. Chatterjee blowing hot and cold at the same time. He said in his opening remarks, when he started speaking, that the habit of painting bodies is an old habit and it should be changed. If he considers that the habit of possessing gold ornaments is bad and it has got to be changed then the restrictions should be there. At the same time when restrictions were put and 14 carat was introduced and there were difficulties to the goldsmiths he also believed in organising processions

and morchas of the goldsmiths and asking for the Gold Control to be scrapped. This is something which one fails to understand. Either you are for gold control completely or you are not for gold control. If you are for gold control then the restriction of 14-carat you must accept. The House knows very well that the restriction of 14 carat had to go on account of the preponderant views both inside and outside the House. That is why the old Act is not there and there is no restriction on the manufacture of gold ornaments of whatsoever purity. The only restriction is that we do not want to have a free entry of gold into our country through smuggling. After all it might be anybody's guess but it is said that more than Rs. 100 crores worth of gold is being smuggled into India, and that is in spite of all the restrictions. Therefore, if you want to make it a completely free market open to all sorts of smuggling, that is a different matter. But you will have to find out and consider ways and means so that the lure of gold goes down, but at the same time we have to keep in view the conditions in our country, the number of people engaged in the gold trade numbering about 2.50 lakhs, and there are more than 12,000 dealers, all those things have been kept in view. That is why according to the present situation the Gold Control Act had to be modified and the 14 carat restriction had to go. Now there is no restriction whatsoever both in the possession and manufacture of gold. . .

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi) : Has it helped in checking smuggling ?

SHRI P. C. SETHI: It has certainly helped in not allowing that much quantity of gold to come in because the smuggling figures go to show that seizures are on the increase. Therefore, as far as smuggling is concerned, it is there and I do not deny it, it has not subsided, but at the same time seizures are going up and we are trying to improve upon the situation. But, as I have said, this is a matter which could be considered separately on merits or demerits of the case. At the present, as I have said in the initial stage, we\* have a very limited object before us, and that is amending the present Act in the light of the Supreme Court judgment, and while amending it we are removing the hardship that were prevalent with regard to the goldsmiths, with regard to the dealers, with regard to vicarious liability, with regard to the licensing policy, with regard to new entrants. Originally it was said that no new

[Shri P. C. Sethi] person would be able to enter. We are liberalising the rules that even a new person could come in.

**श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) :** आपने कहा कि उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने बिल के द्वारा कुछ उपाय सोचे हैं। आप इस बात को देखिए कि एक देहाती आदमी किसी सर्राफ के यहां आकर सोना बेचता है तो उस सर्राफ से आप क्यों कहते हैं—आपने इसके लिए कोई नियम बनाया है या नहीं—कि इसके लिए डिक्लेरेशन दो। गांव का आदमी जो सोना बेचने के लिए आता है उसके बारे में वह कैसे डिक्लेरेशन दे सकता है ?

**श्री पी० सी० सेठी :** यही मैं कह रहा था कि जो इस प्रकार की बात इसमें थी, डिक्लेरेशन आदि का सवाल था उसको मोडीफाई किया गया है इस बिल में जो आपके सामने है। इसी प्रकार सुनारों को लाइसेंस लेने में जो दिक्कत थी, जो सुनारी का धन्धा नहीं करता था उसको भी सुविधा दी गई है, जिन लोगों को लोन दिया गया था और वे लोन वापस कर दें तभी उनको लाइसेंस दिया जा सकता था उसको भी ढीला किया गया है। और भी कई प्रकार की सुविधाएं लाइसेंस डीलर्स और सुनारों को इसमें दी गई हैं। जो एडमिनिस्ट्रिटिव पावर्स ज्यादा थी वे भी एडमिनिस्ट्रिटिव आफिसर से हटा ली गई हैं।

**श्री निरंजन वर्मा :** मेरा मतलब यह था कि जो सर्राफ के यहां गांव वाला सोना लेकर आए, उसमें न मांगते हुए आप सर्राफ से क्यों कहते हैं कि वह डिक्लेरेशन दे। यह कैसे आपने उनकी कठिनाइयों का हल सोचा है ?

**श्री पी० सी० सेठी :** पहले जो इन चीजों के बारे में नियम थे उनको ढीला किया गया है और उनमें सुधार किया गया है।

जहां तक इस बात का सवाल है कि कोई ज़ेवर लाता है सुधार के लिए, उसमें तो किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। जो पहले नियम

था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उसमें सुधार किया गया है।

Therefore, Sir, there is nothing more that I have to say with regard to this. I commend my motion that the Bill be passed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI): The question is :

"That the Bill be passed." *The motion was adopted.*

#### MOTION SEEKING REVOCATION OF PROCLAMATION ISSUED UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO THE STATE OF BIHAR

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : Mr. Yadav. He is not here. Mr. Ramaswamy.

#### RESOLUTION RE PROCLAMATION ISSUED UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO THE STATE OF BIHAR

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : Mr. Vice-Chairman, I beg to move the following Resolution :—

"That this House approves the Proclamation issued by the Vice-President acting as President on the 4th July, 1969, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Bihar."

Mr. Vice-Chairman, after the general elections of 1967 there was no single party with a majority returned to the Assembly of Bihar with enough strength to constitute a stable Government. There have been about six Ministries in Bihar and only one Ministry headed by Mr. M. P. Sinha was in power for 9 months and 25 days, and all other Ministries were in office for various terms between 4 days and 114 days.

There was no stable Government in Bihar and there was also a period of President's rule there from 30-6-68 to 25-2-69. After the mid-term poll, the strength of all the parties remained almost the same as before except for marginal variations. After the mid-term poll, Shri Harihar Singh formed the Government on 26th February,